भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3663

उत्तर देने की तारीख : 24.03.2022

बंद पड़े एमएसएमई

3663. श्री कल्याण बनर्जी:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार की बंद पड़े एमएसएमई को पुन: आरंभ करने हेतु गत तीन वर्षों के दौरान क्या कार्य योजना रही है और इस संबंध में वर्ष 2022-23 के दौरान कितना बजटीय आवंटन किया गया है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)

सरकार ने बंद हो चुके एमएसएमई को फिर से शुरू करने और एमएसएमई क्षेत्र के संवर्धन, विकास और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं। उनमें से कुछ के लिए आत्म निर्भर भारत अभियान के तहत आर्थिक पैकेज के भाग के रूप में घोषणा की गई है, जो निम्नानुसार हैं:-

(i) एमएसएमई के लिए 20,000 करोड़ रुपये का अधीनस्थ ऋण।

(ii) एमएसएमई सहित व्यवसायों के लिए आकस्मिक क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस)।

(iii) आत्मनिर्भर भारत कोष के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपये का इक्विटी समावेशन।

(iv) संयंत्र और मशीनरी या उपस्कर में निवेश और टर्नओवर के संयुक्त मानदंड के आधार पर एमएसएमई का नया संशोधित वर्गीकरण।

(v) 200 करोड़ रुपये तक की सरकारी खरीद के लिए कोई वैश्विक निविदा नहीं होगी।

इसके अलावा, सरकार ने 2022-23 के बजट में एमएसएमई के लिए निम्नलिखित पहलों की घोषणा की है:-

(i) क्रेडिट सुविधा, कौशल और भर्ती प्रक्रिया के लिए उद्यम, ई-श्रम, एनसीएस और असीम (एएसईईएम) पोर्टलों को आपस में जोड़ा जाएगा।

(ii) आकस्मिक क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा और इसके गारंटी कवर को 50,000 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जाएगा और यह अतिरिक्त राशि विशेष रूप से आतिथ्य और तत्संबंधी उद्यमों के लिए निर्धारित की जा रही है।

(iii) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) योजना को एमएसई के लिए 2 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त ऋण की सुविधा और रोजगार के अवसरों को विस्तार देने के लिए आवश्यक धन के साथ रिवैम्प किया जाएगा।

(iv) 5 वर्षों में 6,000 करोड़ रुपये के परिव्यय वाला एमएसएमई के निष्पादन में वृद्धि और गति वर्धन कार्यक्रम (रैम्प) का प्रचालन करना।

2022-23 के दौरान एमएसएमई मंत्रालय को किया गया बजटीय आवंटन 21,422.00 करोड़ रुपये है।

*****